श्री सभापति: आपका प्रश्न क्या है, वह बताइए। ...**(व्यवधान)**...

प्रो. मनोज कुमार झा: यह हमारी पूरी सभ्यता पर तमाचा है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: What is your question?

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Compensation has to be at par with the risk. Maximum compensation has to be paid to those who die.

श्री थावर चन्द गहलोत: माननीय सभापति महादेय, compensation के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1993 में एक निर्णय दिया था, जिसके अनुसार यह आदेशित हुआ था कि सीवरेज टैंक में काम करते हुए जो लोग मर जाते हैं, उन्हें 10 लाख रुपए तक का मुआवजा देने की व्यवस्था सरकार करे। हमारे मंत्रालय ने वह व्यवस्था की है। अभी तक 331 लोग, हमारी जानकारी के अनुसार, सीवरेज टैंक में सफाई करते हुए मारे गए जिनमें से 210 लोगों को हमने 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति की दर से compensation दे दिया है। 47 लोग ऐसे हैं, जिन्हें वहां की राज्य सरकारों ने ठेकेदार से समझौता कराकर, किसी को 3 लाख रुपए दिलवा दिए, किसी को 5 लाख रुपए दिलवा दिए और किसी को 8 लाख रुपए दिलवा दिए। उन सबको भी हम 10 लाख रुपए तक की धनराशि दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। हम संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर निरंतर कोशिश करते रहते हैं।

Misappropriation of funds under Post Matric Scholarship Scheme

*238.SHRI SHAMSHER SINGH DULLO: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to refer to answer to Unstarred Question 442 given in the Rajya Sabha on the 13th December, 2018 and state:

(a) the details of bonafide students who have suffered due to non-release and misappropriation of funds under the Post Matric Scholarship Scheme for SCs, State-wise, especially in Punjab;

(b) the time given to audit agencies to complete their task in Punjab;

(c) whether the State Government of Punjab had requested for release of funds for Post Matric Scholarships for Scheduled Caste and Scheduled Tribe students during the last three years; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI THAAWAR CHAND GEHLOT): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Post Matric Scholarship Schemes for Scheduled Castes is a Centrally Sponsored Scheme, which is implemented by the State Governments/UT Administrations. The Scholarships are awarded to the students by the State Governments/UT administrations to which the applicant belongs. The detailed records of students who applied for /received scholarships are maintained by the concerned State Government/UT Administration. The State-wise total number of beneficiaries, including Punjab under the Post Matric Scholarship Scheme to SC students is at Annexure-I.

(b) As per information received from the Government of Punjab, on 16.6. 2017 the State Government ordered for a special audit of all educational institutions under the Post Matric Scholarship to SC and OBC students, through the Internal Audit Organization (Revenue) of Finance Department of the State. By the end of October 2018, Audit reports of 2059 institutions have been received out of the 3606 institutions under audit. The Audit reports have been sent to the concerned institutions for their comments and reply, of the audit paras.

(c) and (d) The State Government of Punjab had submitted proposals under Post Matric Scheme to SC students during the last three years during 2015-16 to 2017-18 and current year and accordingly the following Central Assistance was released to Punjab Government:

Year	Central Assistance released (₹ in crore)
2015-16	89.30
2016-17	280.08
2017-18	115.73
2018-19	327.39

No community has been specified as Scheduled Tribe in the State of Punjab.

Statement

State-wise Beneficiaries covered under the Post Matric Scholarship Scheme for SC students during the last three years

(in lakhs)

Sl. No.	States/UTs	2015-16	2016-17	2017-18
1.	Andhra Pradesh	6.00	6.85	6.59
2.	Assam	0.40	0.38	0.24

Sl. No.	States/UTs	2015-16	2016-17	2017-18
3.	Bihar	1.55	0.37	0.89
4.	Chandigarh	0.03	0.03	0.02
5.	Chhattisgarh	0.86	0.91	0.96
6.	Daman and Diu	0.00	0.00	0.00
7.	Delhi	0.27	0.21	0.20
8.	Goa	0.00	0.00	0.00
9.	Gujarat	1.59	1.67	1.31
10.	Haryana	0.76	0.94	1.23
11.	Himachal Pradesh	0.49	0.55	0.33
12.	Jammu and Kashmir	0.12	0.04	0.11
13.	Jharkhand	0.34	0.22	0.20
14.	Karnataka	3.18	2.97	3.23
15.	Kerala	1.21	1.31	1.32
16.	Madhya Pradesh	2.88	3.24	3.61
17.	Maharashtra	5.24	4.05	5.41
18.	Manipur	0.04	0.07	0.07
19.	Meghalaya	0.00	0.00	0.00
20.	Odisha	1.79	1.07	2.02
21.	Puducherry	0.05	0.05	0.06
22.	Punjab	3.06	3.09	2.75
23.	Rajasthan	1.44	3.11	1.91
24.	Sikkim	0.00	0.00	0.00
25.	Tamil Nadu	7.58	7.96	7.61
26.	Telangana	2.65	2.78	2.13
27.	Tripura	0.17	0.15	0.15
28.	Uttar Pradesh	9.48	10.95	12.38
29.	Uttarakhand	0.20	0.40	0.70
30.	West Bengal	5.41	6.08	3.83
	TOTAL	56.79	58.62	59.26

श्री शमशेर सिंह ढुलो: चेयरमैन साहब, मेरा specific question था, जिसका मुझे जवाब नहीं मिला। मेरा specific प्रश्न था कि - the details of bonafide students who have suffered due to non-release and misappropriation of funds under the Post Matric Scholarship Scheme for SCs, State-wise, especially in Punjab - मुझे बताया जाए कि कितने students drop-out हुए, ऐसे students जिन्हें scholarship नहीं मिली, उनकी संख्या क्या है? उसका मंत्री जी ने कोई specific जवाब नहीं दिया। आपने कह दिया कि यह State subject है। मंत्री जी ने बोल दिया कि यह स्टेट सब्जेक्ट है। मेरा दूसरा प्रश्न था कि क्या इसमें कोई स्कैम हुआ है, यदि स्कैम हुआ है, तो क्या इसकी जांच के लिए इसको किसी investigating agency को सौंपा गया? उसका भी जवाब नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री सभापति: आपका प्रश्न आ गया।

श्री थावर चन्द गहलोत: सभापति महोदय, इस विषय से संबंधित राज्य सरकारों से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, उसके आधार पर हम प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप रिलीज़ करते हैं। छात्र संबंधित संस्थानों में प्रवेश लेते हैं, तो उसकी जानकारी संबंधित संस्थान द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से हमारे पास भेजी जाती है। जो जानकारी हमारे पास भेजी जाती है, उन छात्रों की संख्या के मान से हमें जितनी छात्रवृत्ति देन चाहिए, उतनी छात्रवृत्ति हम रिलीज़ करते हैं। हमने राज्यवार जो छात्रवृत्ति रिलीज़ की है, उसके आंकड़े मेरे पास है।

श्री सभापति: वे आप माननीय सदस्य को भेज दीजिए।

श्री थावर चन्द गहलोत: अब उन्होंने कहा कि जो योग्य नहीं है... अब योग्य हैं या नहीं हैं, वह तो राज्य सरकार निर्धारित करती है और हमारे पास उसकी लिस्ट भेजती है। जो लिस्ट हमारे पास आती है, उसके आधार पर हम स्कॉलरशिप रिलीज़ करते हैं।

श्री शमशेर सिंह ढुलो: सर, कैग ने इसका ऑडिट किया है और इसमें पंजाब में 500 करोड़ रुपये का स्कैम हुआ है, जिसकी वजह से शेड्यूल्ड कास्ट के लाखों स्टूडेंट्स surprise हुए, उनको dropout कर दिया गया। चूंकि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन जब इसके लिए पैसा सेन्ट्रल गवर्नमेंट दे रही है और पंजाब में इसमें 500 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है, तो उसके बारे में कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा?

श्री थावर चन्द गहलोत: महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, उसमें सत्यता है। कुछ राज्यों में छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण हमारे पास इस संबंध में जानकारी आई, शिकायत आई। हमने प्रयास किया कि उनकी जांच की जाए। उनकी जांच हुई है और जांच में कुछ राज्यों ने यह स्वीकारोक्ति भी की है और यह कहा है कि हम जांच करके पूर्ण प्रतिवेदन आपको देंगे। जब उनके प्रतिवेदन आएंगे ...**(व्यवधान)**...

श्री शमशेर सिंह ढुलो: सर, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज़, you can't stand.

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, मैं बता रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री शमशेर सिंह दुलो: सर, ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: कृपया आप बैठ जाइए। Question No. 239.

श्री थावर चन्द गहलोत: आप मेरी बात तो सुनिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: मंत्री जी, कृपया आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... Question No. 239.

श्री थावर चन्द गहलोत: वह जानकारी आने के बाद ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: मंत्री जी, हो गया। मैं आगे बढ़ गया हूं। अगर कोई नियम का पालन नहीं करेगा, तो मैं उनको मौका नहीं दूंगा। यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

श्री शमशेर सिंह दुलो: *

Impact of BREXIT on Indians migrated to Britain on Portugal passport

*239. SHRI KUMAR KETKAR: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether BREXIT would have any direct impact on India and about two lakh Indians are expected to return to India who have migrated to Britain on Portugal passport; and

(b) if so, what policy measures have been initiated by Government in this regard?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): (a) to (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) BREXIT is still an evolving process. After several months of negotiations, on 25th November 2018, the UK and the EU arrived at a "Withdrawal Agreement" (that covers issues relating to citizens' rights, separation issues, implantation period, financial settlement, governance and protocols) and a "Political Declaration" (sets out the scope and terms of the future UK-EU relationship). Beginning 7th January 2019, the UK Parliament will debate on the BREXIT deal reached between the Theresa May government and the European Union. The final vote on the deal is likely to be taken by the UK Parliament in the week of 14-18 January 2019. Therefore, at this point in time it is not yet certain that the deal in its present form will be approved by the UK Parliament.

*Not recorded.